इण्डिया" शब्दों वाले शीर्षनाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।

(ग) यह प्रतीत होता है कि यह यूनियन तीन गुटों में बंट गई है।

(घ) जी, हां। ट्रेड यूनियन, कानपुर के रजिस्ट्रार के माध्यम से जांच करवाई थी।

(ङ) व्याप्त भ्रांति को देखते हुए भारत सरकार मुद्रणालय अलीगढ़ के प्रबन्धक को कहा गया है कि राजकीय प्रैस मजदूर संघ अलीगढ़ का पदाधिकारियों का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से सम्पर्क न करें।

Nationalisation of Sugar Industry

5943. SHRI R.P. DAS : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state whether in view of larger and rising financial involvement in cane and sugar by the public financial institutions, Government have any intention to nationalise the sugar industry in the near future ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (DR. M.S. SANJEEVI RAO) : The Government has no proposal, under consideration, to nationalise the sugar industry.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हिन्दी का प्रयोग

5944. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को राजभाषा अधिनियम, 1963 के दायरे से बाहर रखा गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके अधीनस्थ सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आवश्यक कार्य राजभाषा हिन्दी में करने में आना-कानी करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) क्या "भा० कृ० अ० प० और उसके संस्थानों को राजभाषा अधिनियम, 1963 को कार्यान्वित करना पड़ेगा" इस मामले पर विधि मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के आधार पर राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने सलाह दी है कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 के अन्तर्गत भा० कृ० अ० प० एक रजिस्टर्ड सोसायटी है, इसलिए इसे एक सरकारी कार्यालय नहीं समझा जा सकता। फिर भी, इसके बावजूद भी, जहां तक संभव है भा० कृ० अ० प० और उसके संस्थानों में राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तरों को देखते हुए, इनका प्रश्न ही नहीं उठता।

Review of Cases of Punishment/Removal of ICAR Staff

5945. SHRI H.N. BAHUGUNA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have seen the tragedy of breakdown of Research and Development work as revealed by judgement of Supreme Court on Indian Council of Agricultural Research (Times of India dated 14 February, 1984) and if so, corrective steps taken/proposed against those found involved and guilty ;

(b) whether Government propose to set up a high powered independent judicial Committee to review all cases of punishment/removal of ICAR staff during the last three years ; and

(c) whether Government propose to involve SACC in this work ?

THE MINISTER OF STATE IN THE